साप्ताहिक
बुलंद गोंदिया
खबरों का आईना
प्रधान संपादक : **अभिषेक चौहान** । संपादक : **नवीन अग्रवाल**
E-mail : **bulandgondia@gmail.com** | E-paper : **bulandgondia.net** | Office Contact No.: **7670079009** | **RNI NO. MAH-HIN-2020/84319**
वर्ष : 5 | अंक : 32 — गोंदिया : गुरुवार, दि. 20 मार्च से 26 मार्च 2025 — पृष्ठ : 4 — मूल्य : रु. 5

जैक सहित सामग्री चोरी

गोंदिया-आमगांव थाने के तहत बनगांव निवासी फिर्यादी सुरज रामनिहोर प्रजापति (33) के घर के जीने के नीचे की सामग्री व फिर्यादी के चाचा के लड़के के ट्रैक्टर का जैक अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया. जिनकी कीमत 5,510 रु. बताई गई है. फिर्यादी की शिकायत पर आमगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

शहर से निकलने वाला कचरा बना सफाई विभाग के अधिकारीयो की अवैध कमाई का जरीया

एक ही घंटा गाड़ी के अनेकों बार वजन, मुख्याधिकारी के मौखिक कार्रवाई के आदेश की अधिकारी उड़ा रहे धज्जियां

बुलंद गोंदिया । गोंदिया नगर परिषद भ्रष्टाचार के पर्याय नाम के रूप में जाने लगी है कोई भी कार्य बिना भ्रष्टाचार के पूरा नहीं होता अब शहर से निकलने वाले कचरे से भी अवैध कमाई की जा रही है जिसमें एक ही घंटा गाड़ी का धर्म कांटे मेंअनेकों बार वजन कर भारी घोटाला किया जा रहा है इस मामले में मुख्याधिकारी द्वारा दोषियों पर कार्रवाई करने के मौखिक आदेश दिए जाने के बावजूद भी संबंधित अधिकारी द्वारा कार्रवाई न कर वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गोंदिया नगर परिषद से निकलने वाले कचरे के लिए टेंडर प्रक्रिया कुछ महापूर्व कर उसका कार्य आदेश भी संबंधित ठेकेदार को दिया गया था। नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत प्रतिदिन 60 से 65 टन कचरा निकालने का अनुमान है जिसका डीपीआर भी नगर परिषद द्वारा बनाया गया था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आपसी साठ गाठ कर शहर से निकलने वाले कचरे का दो से तीन बार वजन कर निकलने वाले कचरे की मात्रा अधिक बताई जा रही है। जिसमें 100 से अधिक टन कचरे का बिल बनाया जाएगा जिसमें बड़े पैमाने पर अधिकारियों द्वारा संबंधित ठेकेदार से लेनदेन कर नगर परिषद के साथ-साथ शहर वासियों की टैक्स की राशि को भी चूना लगाया जाएगा तथा शहर के विकास की राशि इन भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ेगी जिन अधिकारियों पर शहर को स्वच्छ सुंदर रखने की जिम्मेदारी है वे ही नगर परिषद को भ्रष्टाचार की गंदगी से लबालब कर रहे हैं।

उल्लेखनीय की गोंदिया शहर का निकलने वाला प्रतिदिन का कचरा घंटा गाड़ियों में संकलन कर गोंदिया कृषि उत्पन्न बाजार समिति में स्थित धर्मकांटे में उसका वजन कर हिरडामाली के डंपिंग यार्ड में भेजा जाता है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार 11 मार्च को गोंदिया नगर परिषद के मुख्याअधिकारी को गुप्त जानकारी प्राप्त हुई कि एक ही घंटा गाड़ी का अनेकों बार वजन कर कचरे की मात्रा को बढ़ाई जा रही है। जिस पर मुख्याधिकारी धर्म कांटे पर पहुंचकर मामले की जांच कर स्वच्छता विभाग के राजपत्रित अधिकारी उप अभियंता नितिन गौरखेड़े को घटनास्थल पर बुलाकर इस मामले में दोषी शहर स्वच्छता समन्वयक मानकर जो की ठेकेदारी पद्धति पर गत अनेक वर्षों से कार्यरत है उसे पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। इस मामले को करीब 8 दिन हो जाने के बावजूद भी संबंधित अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई न कर वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह कर दोषी कर्मचारियों को बचाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्याधिकारी के मौखिक आदेश का पालन नहीं शहर से निकलने वाले घंटा गाड़ियों के वजन की जिम्मेदारी शहर सामान्य मानकर नामक कर्मचारी की है जो ठेकेदारी पद्धति पर कार्यरत है उसे पर कार्रवाई करने के मुख्याधिकारी द्वारा मौखिक रूप से आदेश दिए गए थे लेकिन मुख्या धिकारी के आदेश के बावजूद भी स्वच्छता विभाग के अभियंता नितिन गौर खेड़े द्वारा अब तक कार्रवाई नहीं की गई जिससे यह साबित होता है कि संबंधित अधिकारी का भी हित इससे लगा हुआ है तथा मुख्याधिकारी के आदेश का पालन न करना नगर परिषद की दयनीय स्थिति को उजागर करता हैतथा मानकर नामक कर्मचारी को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अधिकारी भी बने ठेकेदार गोंदिया नगर परिषद में इसके पूर्व जनप्रतिनिधियों तथा राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर ही ठेकेदारी करने के आरोप लगाते आए हैं लेकिन अब संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आपसी साठ गाठ कर अपने मित्रों व परिचितों के नाम पर ठेकेदारी कर रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार की जड़ नगर परिषद में काफी विस्तृत रूप से फैल चुकी है।

धर्मकांटे पर तैनाती धर्म कांटे में आकस्मिक पहुंचकर मुख्य अधिकारी द्वारा जांच किए जाने पर संबंधित दोषी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी तथा इसके पश्चात धर्म कांटा हिड़माली डंपिंग यार्ड में नगर परिषद के अधिकारियों की नियुक्ति की है। अब तक कितना घोटाला शहर में चर्चा का बाजार गर्म गोंदिया नगर परिषद के कचरा वजन में अब तक कितना घोटाला किया गया है क्या वरिष्ठ अधिकारियों व जिला अधिकारियों महोदय द्वारा इस मामले में एक जांच समिति बैठल कर निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी इस संदर्भ में शहर के नागरिकों में चर्चा चल रही थी चल रही है

धर्मकांटे पर नियुक्ति किन्तु कार्रवाई का कोई निर्देश नहीं मुख्याधिकारी द्वारा धर्मकांटे पर उपस्थित रहकर कांटे की जांच व वजन पर के नजर रखने का निर्देश दिया है तथा किसी भी प्रकार की कार्रवाई का मौखिक आदेश नहीं दिया।

- नितिन गौरखेड़े अभियंता पानी व स्वच्छता नगर परिषद गोंदिया।

श्रीराम जन्मोत्सव समिति ने सौंपा ज्ञापन शोभायात्रा का समय बढ़ाने जिलाधीश से मांग

गोंदिया-प्रभु श्री राम जन्मोत्सव पर परंपरागत रूप से आयोजित शोभायात्रा का समय रात्रि 12 बजे तक करने के लिए श्रीराम जन्मोत्सव समिति के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधीश प्रजीत नायर से मुलाकात कर इस मामले में ध्यानाकर्षण किया. जिलाधीश नायर ने बताया कि उन्हें भी राज्य सरकार से इस आशय का मेल प्राप्त हुआ है. प्रतिनिधि मंडल को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी देते हुए उन्होंने कहा कि वह निश्चित तौर पर इस बात को समझते हैं और समय को बढ़ाने के लिए निर्देश जारी कर देंगे. प्रतिनिधि मंडल मे श्री राम जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष हेमेंद्र पोद्दार, स्नेहल पटेल, अपूर्व अग्रवाल, नितिन जिंदल, विक्की चंद्राना, सौरभ बजाज, संदीप आष्टीकर, रवि रामटेककर, उपेंद्र लांजेवार, विनोद आगाशे, अजय यादव, योगेश पशीने, आदि का समावेश था.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात

गडचिरोली मायनिंग हब, नागपुर हवाई अड्डा, स्थानीय निकायों के लिए वित्त आयोग निधि आदि के संबंध में सकारात्मक चर्चा

नई दिल्ली/गोंदिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उनके साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

राज्य सरकार ने गढ़चिरौली में इस्पात क्षेत्र में बड़ी पहल की है और गढ़चिरौली अब देश की इस्पात नगरी के रूप में विकसित हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केंद्र को गढ़चिरौली को खनन केंद्र के रूप में विकसित करने में सहयोग करना चाहिए। नागपुर एयरपोर्ट पर भी काम तेज कर दिया गया है और देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार से जुड़े कुछ मुद्दों पर भी चर्चा की। इससे एयरपोर्ट के काम में आ रही बाधाएं जल्द ही दूर हो जाएंगी। चर्चा में एक विषय यह था कि स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग से यथाशीघ्र धनराशि प्राप्त होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन सभी मामलों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्व श्रव्य, दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित करने का अवसर महाराष्ट्र को देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। यह शिखर सम्मेलन 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर आईआईटी की तर्ज पर मुंबई में भी आईआईसीटी (भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान) की स्थापना की जाएगी और इसके लिए केंद्र सरकार धनराशि भी उपलब्ध कराएगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया।

कवयित्री कमलेश तिवारी का सत्कार

बुलंद गोंदिया। संयुक्त काव्यसंग्रह कलरव कमलेश शशि तिवारी के विगत दिनों प्रकाशन एवं सतत काव्य लेखन तथा पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन पर गरिमा महिला संगठन की पदाधिकारी सदस्य महिलाओं ने नगर की वरिष्ठ कवयित्री सौ. कमलेश तिवारी के निवास स्थान पर जाकर उनका पुष्पगुच्छ प्रदान कर सत्कार किया एवं उनके स्वस्थ, दीर्घायु जीवन की शुभकामनायें दी। संगठन अध्यक्ष मौसमी भालाधरे, सचिव वर्षा मानकर, कोषाध्यक्ष धनंजयी काकडे, भारती सोनवाने,सायली चौरे एवं अन्य सदस्याएं उपस्थित थीं।

औरंगजेब की कब्र सरकार हटाए अन्यथा बजरंग दल कार सेवा कर हटाएगा -मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

बुलंद गोंदिया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने पूरे राज्य में अभियान चलाया है इसी के अंतर्गत गोंदिया जिला बजरंग दल द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की गई की सरकार द्वारा कब्र हटाने की कार्रवाई की जाए अन्यथा बजरंग दल वह विश्व हिंदू परिषद द्वारा बाबरी मस्जिद की तरह कार सेवा कर कब्र को हटाएगा ।

गौरतलब है की बाबर के वंशज मुगल शासन औरंगजेब की कब्र छत्रपति संभाजी नगर से हटाने को लेकर को लेकर 17 मार्च सोमवार को पूरे राज्य में विश्व हिंदू परिषद वह बजरंग दल द्वारा विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिलाधिकारियों को सोपा गया। इसी अभियान के अंतर्गत गोंदिया जिला बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा गया कि सरकार द्वारा कब्र को हटाया जाना चाहिए अन्यथा बाबरी मस्जिद जैसी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई जिसमें का र सेवा कर कब्र को हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि विदेशी आक्रमणकारी बाबर के वंशज औरंगजेब की कब्र छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है किंतु औरंगजेब की मृत्यु अहिल्या देवी नगर में हुई थी तथा बाद में उसके शव को वहां की कब्र से निकलकर छत्रपति संभाजी नगर में दफनाया गया था। क्रूर शासक औरंगजेब मुगल शासक औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसकी क्रूरता के किस्से आज भी मौजूद है। जिसमें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या गुरु गोविंद सिंह के दो बच्चों को दीवार में इसलिए चुनवा दिया गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज को क्रूरता पूर्वक अमानवीय तरीके से तड़पा तड़पाकर हत्या की साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस ,मथुरा के मंदिर का विध्वंस, गुजरात के सोमनाथ मंदिर में लूटपाट, त्रंबकेश्वर मंदिर जेजूरी गढ़ पर हमला करने के साथ ही औरंगजेब द्वारा हिंदुओं को इस्लाम कबूल कर मुस्लिम बनाने का अभियान चलाया गया था सिर्फइसलिए जजिया कर लगाया था। हजारों हिंदुओं की हत्या करवाकर शवो का गांव के बाहर देर लगावा देता जिससे हिंदुओं में दहशत निर्माण हो तथा वह इस्लाम स्वीकार करें। भारतीयों पर अत्याचार की प्रतीक कब्र मुगल शासक औरंगजेब ने तलवार के दम पर धर्मांतरण करवाया ऐसे क्रूर शासक का स्मारक कब्र स्वतंत्र भारत में गुलामी वह यातना के प्रतीक के रूप में प्रतीत होती है सरकार व शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं की कब्र को पूरी तरह नष्ट किया जाए तथा देश में विदेशी आक्रमण कार्यों के प्रतिको नष्ट किया जाए जिसकी संपूर्ण कार्रवाई सरकार द्वारा नियम से की जाए यदि शासन द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल व हिंदू समाज छत्रपति संभाजी नगर के साथ मिलकर कार सेवा के लिए मार्च करेंगे। आंदोलन व निवेदन देते समय देवेश मिश्रा, प्रान्त सहमंत्री, नवीन जैन, प्रान्त संयोजक, मुकेश उपराडे, जिला सहमंत्री, महेंद्र देशमुख, जिला सत्संग प्रमुख, अंकित कुलकर्णी, जिला संयोजक, हार्दिक जिवानी, जिला साप्ताहिक मिलन प्रमुख, विठ्ठल कोठेवार, जिला मंदिर अर्चक प्रमुख, प्रमोद कोठारी, नगर अध्यक्ष, हरीश अग्रवाल, नगर मंत्री, दिलीप रक्से, नगर सहमंत्री, जितेंद्र राणा, दिलीप कुंगवानी, विशाल शुक्ला, अनिल सदन, भोला कोकाटे, भूमेश डहारे, ओमप्रकाश तिवारी, सागर परिहार, आशीष टेंभरे, कोमल रहांगडाले, भूपेंद्र श्रीवास, अनिल बिसेन, हितेश कोडवानी, बन्नी कनोजिया, शैलेन्द्र मिश्रा, संजय पटेल, अशोक हेमने, अजय यादव, अजय जैन, बबलू गभने, लवकेश मिश्रा, आशीष कटरे, पंकज मिश्रा, प्रदीप बिसेन, कोमल धोटे, नितिन जिंदल, रोहित श्रीभाद्रे, अजय अग्रवाल, सोनू गौतम, ओमप्रकाश तिवारी, समरित नशीने, आदि हिंदू समाज उपस्थित थे।

मारपीट, मामला दर्ज

गोंदिया-सालेकसा थाने के तहत शिवारीटोला निवासी फिर्यादी अशोक राखढु पंधरे (42) व आरोपी देवराम अलालीराम पुजारी (34) के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था. उसी द्वेष को मन में रखकर आरोपी ने फिर्यादी के साथ लाठी से मारपीट की. वहीं गालीगलौज कर आगे मारने की धमकी दी. फिर्यादी की शिकायत पर सालेकसा पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच हवलदार बिसेन कर रहे हैं.

बाइक दुर्घटना में महिला की हुई मौत

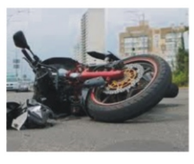

गोंदिया-गोरेगांव थाने के तहत कुरहाड़ी निवासी फिर्यादी पुरुषोत्तम बाबुलाल पटले (28) की सास योगराज तुकाराम राणे की मोटरसाइकिल क्र. एमएच 40 - बीटी 4931 से नागपुर से अपने गांव घोटी आ रही थी. इसी दौरान मुरदोली से मुंडीपार मार्ग पर मोटरसाइकिल स्लीप हो गई. जिसमें फिर्यादी की सास की मौत हो गई. फिर्यादी की शिकायत पर गोरेगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच महिला पुलिस उपनिरीक्षक प्रीति लांडे कर रहे हैं.

संपादकिय...

शीर्षता की सूची में

भारत के प्रमुख शैक्षिक, प्रौद्योगिकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए बेहद अच्छी खबर है। अब भारत भी शीर्षता की वैश्विक सूची में उपस्थित है। देश के 9 संस्थान शीर्ष 50 संस्थानों की जमात में शामिल हैं और 79 भारतीय विश्वविद्यालयों को भी शीर्षता के तौर पर चिह्नित किया गया है। बीते साल यह संख्या 69 थी। एक दौर ऐसा भी था, जब हमारे संस्थान और विश्वविद्यालय 500 शीर्ष की सूची में भी नहीं आते थे। उसमें भी कोई राजनीतिक और भारत को 'पिछड़े देश' के तौर पर आंकने की मानसिकता रही होगी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भारत शीर्ष देशों की श्रेणी में रहा है। नालंदा, तक्षशिला इसके सांस्कृतिक उदाहरण रहे हैं, लेकिन वक्त के मुताबिक, शिक्षा के आयाम और क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। आज कृत्रिम बौद्धिकता, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग का बिल्कुल परिवर्तित युग है, लिहाजा रोजगार की अपेक्षाएं भी बदली हैं। सुखद और प्रोत्साहित खबर यह है कि भारतीय विश्वविद्यालयों के 24 इंजीनियरिंग संस्थान, सोशल साइंस के 20 और प्राकृतिक विज्ञान के 19 संस्थान शीर्षता की सूची में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह उपलब्धि ऐसे समय हासिल हुई है, जब बहुधा रपटों और सर्वेक्षणों के निष्कर्ष सामने आ रहे थे कि भारतीय स्नातकों में कौशल, हुनरमंदी का घोर अभाव है। अब क्यूएस रैंकिंग सूची में विश्वविद्यालयों और संस्थानों के कौशल संबंधी प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है, नतीजतन स्नातकों की वरीयता में नियोक्ताओं (एंप्लायर) की अपेक्षाओं और दृष्टिकोण में भी काफी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हालिया साक्षात्कार में कहा है कि दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन भारत के बिना 'एआई' (कृत्रिम बौद्धिकता) अधूरी है हालांकि भारत सरकार में कौशल मंत्रालय का गठन प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्र रूप से किया था, लेकिन कौशल के नाम पर कुछ भाषण देना या सुनना के अलावा हम ठोस और व्यावहारिक तौर पर इसे आंदोलन नहीं बना सके हैं, लिहाजा हमारे युवा वैश्विक ही नहीं, घरेलू आधार पर भी पिछड़े हैं। बहरहाल हम शीर्षता की जमात में शामिल हो गए हैं, लेकिन क्यूएस 2025 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारत ज्ञान और अर्थव्यवस्था का शीर्ष गंतव्य, गढ़ बनने में अब भी पीछे है। यह भी रेखांकित किया गया है कि भारत के संभ्रांत और विशिष्ट विश्वविद्यालयों को अपने छात्रों के सीखने के अनुभवों में सुधार की गुंजाइश बेहद जरूरी है। उसी के बाद वे वैश्विक तौर पर अपनी उपस्थिति साबित कर पाएंगे। छात्रों के सीखने के अनुभवों और उन्हें प्रशिक्षित बनाने में बेहतर शिक्षकों, निरंतर निरीक्षण और पाठ्यक्रम विकास आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सूची में शामिल विश्वविद्यालय और संस्थान क्यूएस वरीयता प्रणाली के ऐसे मानदंडों पर लगभग खरे साबित हुए हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षकों और उनके काम करने की माकूल स्थितियां आज भी हमारी उच्च शिक्षा के लिए बुनियादी समस्याएं बनी हुई हैं। संस्थानों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं अथवा छात्रों के अनुपात में अध्यापक बहुत कम हैं।

एग्रीस्टैक योजना- कृषि में डिजिटल क्रांति-एग्रीस्टैक क्या है?

एग्रीस्टैक किसानों के लिए एक डिजिटल पहचान पत्र प्रणाली है। इसमें प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूनिक फार्मर आईडी) दी जाती है। इस नंबर के आधार पर किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगा। फसल ऋण, बीमा, सब्सिडी, खाद और बीज से जुड़े सभी मामलों में भी यह योजना उपयोगी साबित होगी। केंद्र और राज्य सरकारों ने कृषि को आधुनिक बनाने और किसानों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए %एग्री स्टैक% योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से किसानों का डिजिटल डेटाबेस बनाकर कृषि सेवाओं को तेज और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। फसल बीमा योजना सहित कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में बढ़ते भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को रोकने के लिए राज्य में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित %एग्रीस्टैक% योजना को मजबूत किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य में 38 लाख 58 हजार 702 किसानों को पहचान पत्र दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश के बाद, महाराष्ट्र किसान पहचान पत्र जारी करने में अग्रणी हो गया है। इसका उद्देश्य अप्रैल तक एग्रीस्टैक योजना के तहत राज्य के सभी किसानों यानी 1 करोड़ 19 लाख खाताधारकों को पहचान पत्र प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं, कृषि सलाह, मौसम, बाजार भाव, बाजार की स्थिति, देश में स्थिति आदि की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी, जिससे किसानों का समय बचेगा।

योजना की प्रकृति एवं लाभ ,प्रत्यक्ष लाभ अंतरण(डीबीटी)

पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, प्राकृतिक आपदा राहत आदि सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जमा की जाएंगी। इससे बिचौलियों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

फसल ऋण और बीमा के लिए सरल प्रक्रिया

फसल बीमा और ऋण प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पहचान पत्र के रूप में बिल्कुल उपयुक्त होगा। एग्रीस्टैक के रिकार्ड के अनुसार, ऋण स्वीकृति तीव्र गति से की जाएगी।

कृषि के लिए सब्सिडी और अन्य सुविधाएं

किसानों को खाद, बीज और दवाइयों पर सीधे सब्सिडी मिलेगी। मौसम पूर्वानुमान, मृदा परीक्षण और सिंचाई योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी।

प्राकृतिक आपदा और कृषि सहायता

सूखा, ओलावृष्टि, भारी वर्षा या अन्य आपदाओं से हुए नुकसान की सहायता के लिए किसानों की जानकारी पहले से ही उपलब्ध होगी, जिससे सहायता का वितरण तेजी से होगा। इस योजना के पंजीकरण के लिए जिले के प्रत्येक गांव में शिविर आयोजित किए गए हैं। यह पंजीकरण राजस्व, कृषि एवं जिला परिषद विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया जाएगा।

दस्तावेज़ आधार कार्ड,आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर

पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क है, इसलिए किसान किसी भी अफवाह में फंसे बिना पंजीकरण कराएं।

पंजीकरण प्रक्रिया कैसे करें ?

जिले में. 8 मार्च से 13 मार्च 2025 तक एक विशेष एग्रीस्टैक पंजीकरण सप्ताह का आयोजन किया गया। जिले के प्रत्येक गांव में शिविर आयोजित किये गये। यह पंजीकरण राजस्व, कृषि एवं जिला परिषद विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया जाएगा।

किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अपने गांव के सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) पर पंजीकरण कराना चाहिए ङ्क

!इसके साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। पात्र लाभार्थी अपने गांव की उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-पॉस मशीन पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करा लें। साथ ही, यह प्रक्रिया राज्य सरकार के %मेरा ई-केवाईसी% मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे पूरी की जा सकेगी।

ई-केवाईसी पूरा न करने पर सरकारी खाद्यान्न लाभ बंद हो जाएगा, इसलिए यह प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जानी चाहिए।

आयुष्मान भारत कार्ड के अवसर

इस अवसर का लाभ उठाते हुए नागरिकों को अपना आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड की फोटोकॉपी, राशन कार्ड की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर।

इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में गोंदिया जिले के प्रत्येक गांव में शिविर चल रहे हैं। नागरिको से प्रशासन ने अपील की है कि वे आकर अपना राशन कार्ड, ई-केवाईसी, एग्रीस्टैक और आयुष्मान कार्ड ले लें।

किसानों के लिए महत्वपूर्ण मामला

कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषि आदानों एवं अन्य सेवाओं का लाभ लेने, बाजार की जानकारी, कृषि कार्य के संबंध में कृषि विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए यूनिक किसान आईडी की आवश्यकता होगी। कृषि भूमि की खरीद-बिक्री के लिए इस विशिष्ट किसान आईडी की आवश्यकता होगी। इतना ही नहीं, इस यूनिक किसान आईडी के जरिए सरकार एक क्लिक पर यह भी जान सकेगी कि किस किसान के पास कितनी जमीन है, कहां है और वह किन योजनाओं का लाभ ले रहा है। इस विशिष्ट किसान आईडी के जरिए सरकार को एक क्लिक पर ही यह जानकारी मिल सकेगी कि राज्य में कितने किसानों ने चालू सीजन में कौन सी फसल उगाई है। इसलिए, कृषि विभाग फोन पर विशिष्ट फसलों के किसानों को विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम होगा। जियो-रेफरेंसिंग के माध्यम से प्रत्येक किसान के खेत का डिजिटल मानचित्र उपलब्ध होगा। सरकार को उम्मीद है कि राजस्व, कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी इस योजना में सहयोग करेंगे, यदि वे आकर पंजीकरण के लिए आधार संख्या मांगेंगे। गोंदिया जिले के सभी किसान अपने गांव में पंजीकरण शिविर में जाकर 8 मार्च से 13 मार्च 2025 तक एग्रीस्टैक के लिए पंजीकरण कराएं। यह योजना किसानों के आर्थिक एवं तकनीकी सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बिना किसी गलतफहमी के आप आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने गांव के सीएससी केंद्र पर जाएं और पंजीकरण कराएं। सरकार की इस पहल से कृषि में एक नया आधुनिक दृष्टिकोण आएगा और किसानों को डिजिटल सेवाओं का अधिक लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको अपने गांव के सीएससी केंद्र, राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों ने कृषि को आधुनिक बनाने और किसानों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए %एग्री स्टैक% योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से किसानों का डिजिटल डेटाबेस बनाकर कृषि सेवाओं को तेज और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। जिला कलेक्टर प्रजित नायर ने गोंदिया जिले के सभी किसानों से इस योजना में भाग लेने की अपील की है। **संकलन-जिला सूचना कार्यालय, गोंदिया**

स्वच्छ जल जीवन है, पर बिगड़े तो हाहाकार है-विश्व जल दिवस विशेष

जल प्रकृति की सबसे बड़ी देन है क्योंकि संपूर्ण जीव सृष्टि का आधार पानी है, इसके बिना जीवन की कल्पना बेमानी हैं। जल समृद्धता से जंगल, पेड़-पौधे, वन्यजीव समृद्धता बढ़ती है, सबको शुद्ध जल और शुद्ध प्राणवायु मिलती है, ऋतु चक्र, मौसम और प्रकृति में संतुलन बना रहता है, खाद्यान की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ता है, प्रकृति के प्रत्येक घटक पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। जल शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में सबको मिले तो समृद्धि निश्चित है, परंतु यह जल अपर्याप्त और प्रदूषित है, तो फिर यह जल विनाश का कारण है। विश्व का लगभग 97 प्रतिशत जल खारा है या पीने योग्य नहीं है। भारत देश में विश्व की सबसे ज्यादा 18 प्रतिशत जनसंख्या है, परंतु इसके मुकाबले दुनिया के जल संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत भारत में है, जो इसे पानी की कमी वाले देशों में से एक बनाता है, इसका खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है क्योंकि हर साल लाखों भारतीय दूषित पानी से बीमार होकर मरते हैं। द लैंसेट के एक अध्ययन के अनुसार, 2019 में जल प्रदूषण के कारण भारत में 500,000 से अधिक लोगों की मौत हुई।

हर साल 22 मार्च को दुनियाभर में 卐विश्व जल दिवस卐 पानी के महत्व और वास्तविक स्थिति पर जागरूकता हेतु मनाया जाता हैं। इस साल 2025 की थीम %ग्लेशियर संरक्षण% है, जो भविष्य के लिए जमे हुए इन ग्लेशियर के जल संसाधनों का संरक्षण करने पर केंद्रित हैं। ग्लेशियर यह पानी का विशाल भंडार है, जो उसका पिघला हुआ पानी पेयजल, कृषि, उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है, परंतु ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और इस कारण बड़े-बड़े ग्लेशियर पिघल रहे है एवं वह पिघला हुआ शुद्ध जल समुद्र का स्तर बढ़ा रहे हैं। तेजी से पिघलते ग्लेशियर जल प्रवाह में अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं, जिसका लोगों और ग्रह पर गहरा प्रभाव पड़ रहा हैं। कार्बन उत्सर्जन में वैश्विक कमी और ग्लेशियरों के सिकुड़ने के अनुरूप स्थानीय नीतियों की आवश्यकता हैं।

विश्व आर्थिक मंच ने 15 जनवरी, 2025 को जारी वार्षिक वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के 20वें संस्करण में चेतावनी दी है कि भारत देश के सामने एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि अगले दो वर्षों (2025-2027) में पानी की कमी देश के सामने सबसे गंभीर खतरा बनकर उभरेगी। शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान ने

एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार, सबसे बड़े वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार, प्रदूषित वायु औसत जीवन प्रत्याशा को 3.6 वर्ष तक कम कर रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हर साल 3,575,000 लोग जल-संबंधी बीमारियों से मरते हैं। यह हर 10 सेकंड में एक मौत के बराबर हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सरकार को 2024 के एक अध्ययन की जानकारी दी है, जिसमें पाया गया है कि पंजाब में प्रदूषित नदी-नालों के पास रहने वाले लोगों में कैंसर होने की संभावना अधिक होती हैं। जल प्रदूषण में औद्योगिक कूड़ा, मल, माइक्रोबियल प्रदूषण, निलंबित पदार्थ, रासायनिक प्रदूषण, घुलनशील प्रदूषक, रेडियोधर्मी कचरे, थर्मल प्रदूषण, मानव अपशिष्ट, औद्योगिक उद्यम, ऑयल पॉल्यूशन, कृषि प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, खनन, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट, अम्ल वर्षा जैसे कारण विशेष है, पानी के संपर्क में आते ही यह विशेष कारण जल को विषैला बना देते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 2021 में 2 बिलियन से ज्यादा लोग पानी की कमी वाले देशों में रहते थे। 2022 में, वैश्विक स्तर पर कम से कम 1.7 बिलियन लोग मल से दूषित पेयजल स्रोतों का उपयोग करते थे। मल संदूषण के कारण पेयजल में सूक्ष्मजीवों का संदूषण, पेयजल सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। 2021 में, 251.4 मिलियन से अधिक लोगों को सिस्टोसोमियासिस के लिए निवारक उपचार की आवश्यकता थी। सूक्ष्मजीवीय रूप से दूषित पेयजल से डायरिया, हैजा, पेचिश, टाइफाइड और पोलियो जैसी बीमारियां फैल सकती है, तथा अनुमान है कि इससे हर साल डायरिया से संबंधित लगभग 505,000 मौतें होती हैं। 296 मिलियन लोग असुरक्षित कुओं और झरनों से पानी भरते है और 115 मिलियन लोग झीलों, तालाबों, नदियों और झरनों से अनुपचारित सतही जल एकत्र करते हैं।

तीव्र शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण जल संसाधनों का प्रदूषण बढ़ गया है, जिससे वे उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं। अकुशल कृषि पद्धतियां, रसायनों का अत्यधिक उपयोग, भूजल का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन, खराब जल प्रबंधन और उचित बुनियादी ढांचे की कमी जैसे कई कारक जल की कमी के संकट को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व बैंक के कुछ आंकड़े अनुसार, भारत देश में 163 मिलियन भारतीयों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है, 210 मिलियन भारतीयों को बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच नहीं हैं। 21 प्रतिशत संक्रामक रोग असुरक्षित जल से संबंधित है, भारत में प्रतिदिन पांच वर्ष से कम आयु के 500 बच्चे दस्त से मरते हैं। भारत की आधी से अधिक नदियाँ अत्यधिक प्रदूषित हैं, तथा कई अन्य नदियाँ आधुनिक मानकों के अनुसार असुरक्षित स्तर पर हैं। शहरों से बहनेवाली नदियाँ नालों का स्वरूप धर चुकी हैं। नीति आयोग की 2018 समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षित जल की अपर्याप्त पहुंच के कारण हर साल लगभग दो लाख लोग मर जाते हैं। 2030 तक लगभग 600 मिलियन लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, जो भारत देश की अनुमानित जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत होगा।

वॉटर गैर-लाभकारी संगठन बताती है कि, भारत देश में 1.4 बिलियन की आबादी में से आज भी 35 मिलियन लोगों के पास सुरक्षित जल तथा 678 मिलियन लोगों के पास सुरक्षित स्वच्छता तक पहुंच नहीं है, सुरक्षित जल और स्वच्छता की कमी के कारण हर वर्ष दस लाख से अधिक लोग मरते हैं, तथा हर दो मिनट में एक बच्चा जल या स्वच्छता से संबंधित बीमारियों के कारण जान गंवाता है। विश्व के 29 प्रतिशत स्कूलों में स्वच्छ जल और शौचालय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव है। बुनियादी जल और स्वच्छता की कमी के कारण हर वर्ष विश्वभर में 260 बिलियन डॉलर बर्बाद हो जाते हैं। विश्व की कम से कम 50 प्रतिशत जनसंख्या वर्ष में कम से कम एक माह तक अत्यधिक जल संकट में रहते हैं। दुनियाभर में महिलाएं और लड़कियां प्रतिदिन कई किलोमीटर तक पानी के लिए भटकती है और पानी इकट्ठा करने में 200 मिलियन घंटे तक बिताती हैं। घर पर सुरक्षित जल और स्वच्छता की उपलब्धता, व्यतीत किए गए समय को बचाती है, जिससे परिवारों को शिक्षा और कार्य के अवसरों को प्राप्त करने के लिए अधिक समय मिलता है, जिससे उन्हें गरीबी के चक्र को तोड़ने में मदद मिलेगी।

जब तक किसी चीज की कमी न हो, तब तक मनुष्य को उस चीज की कीमत नहीं समझतीं, जल से जीवन है, अधिकतर लोगों को पानी प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके हिसाब से दुनिया में पानी सहज उपलब्ध है, शायद इसलिए पानी का मोल लोग नहीं समझते हैं। किसी कठिन परिस्थिति में अगर पानी न मिलें तो तन-मन व्याकुल हो उठता हैं, ग्रीष्म ऋतु के मौसम में शहरों में किसी कारणवश एक दिन भी जनता को पानी न मिलें तो हाहाकार मच जाता है, तब दुनिया की सबसे कीमती चीज पानी लगती हैं। आज जो पानी हमें सहज उपलब्ध हो रहा है, करोड़ों लोग उस पानी के लिए रोज दर-दर भटकते है, अपना कीमती समय पानी इकट्ठा करने में गवाते है, फिर भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल नसीब नहीं होता, मज़बूरी में अशुद्ध जल के उपभोग के कारण घातक बीमारियों का शिकार होकर असमय मौत के आगोश में चले जाते हैं। पानी की कमी के कारण पशु-पक्षियों, वन्यजीवों का तो अधिक बुरा हाल होता है। पानी का अपव्यय और योग्य प्रबंधन द्वारा संग्रहण, इसके तरीके हम सभी जानते है, लेकिन गंभीरता नहीं समझतें। अनमोल पानी का महत्व समझें, शुद्ध जल पर प्रत्येक व्यक्ति और जीवों का बराबरी का अधिकार है, सबको शुद्ध जल मिलें यह हम सबकी जिम्मेदारी हैं। जल बचाएं, अनमोल जीवन बचाएं।

डॉ. प्रितम भि. गेडाम

वन भूमि, मुरुमपट्टा वितरित करें,जाति वैधता प्रमाण पत्र रद्द किये गए सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्यों की नियुक्ति पर पुनर्विचार करें

पूर्व मंत्री व विधायक राजकुमार बडोले ने बजट सत्र में विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार का किया ध्यानाकर्षण

बुलंद गोंदिया। राज्य विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और राज्य के पूर्व मंत्री और अर्जुनी मोरगांव विधानसभा के विधायक राजकुमार बडोले ने विभिन्न मुद्दों पर महाराष्ट्र विधानसभा में अपनी आवाज उठाई। पिछले कई वर्षों से किसान वन भूमि का पट्टा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिन लोगों को वन भूमि के पट्टे मिले हैं, उन्हें न केवल सरकार से ऋण नहीं मिल पा रहा है, बल्कि वे सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हैं। उन्होंने विधानसभा में मांग की कि कई लोगों को वन भूमि के पट्टे दिए जाएं, क्योंकि उन्हें अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं। इसके साथ ही मुरुम की रॉयल्टी जिलाधिकारी के पास लंबित है और कम से कम कुछ गांवों में मुरुम बेल्ट दी जानी चाहिए जो इको सेंसिटिव जोन में नहीं आते हैं क्योंकि अगर कोई किसान अपने खेत में मिट्टी खोदता भी है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। राजकुमार बडोले ने मांग की कि इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने विधानसभा में यह भी राय व्यक्त की कि नवेगांव बांध में 800 पेड़ों की हत्या की जांच की जानी चाहिए।

जिन सरपंचों, ग्राम पंचायत सदस्यों के जाति वैधता प्रमाण पत्र रद्द किए गए थे, उन पर पुनर्विचार करें

जिलाधिकारी ने जाति वैधता प्रमाण पत्रों के सत्यापन में खामियां पाए जाने के बाद 208 सरपंचों और सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी। सदस्यता रद्द करते समय 36 में से 32 स्थानों पर जाति सत्यापन समिति का कोई पदाधिकारी नहीं है। आदिवासी विभाग की नवगठित समिति में कोई अधिकारी नहीं है। रद्द किये गये 208 मामलों में से 150 से अधिक मामले आदिवासी समुदायों से संबंधित थे। साथ ही, मामलों की जानकारी एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाती है, जिसे कई लोग पढ़ नहीं पाते। इसलिए, केस रद्द करते समय जिला मजिस्ट्रेट ने किसी अधिकारी को नहीं बुलाया और सीधे केस रद्द कर दिया। राजकुमार बडोले ने मांग की है कि सरकार उन लोगों पर पुनर्विचार करे जिनकी सदस्यता इस कारण रद्द की गई है।

इटियाडोह क्षेत्र में वनों की कटाई की जाए

इटियाडो ह बांध का निर्माण 1970 के दशक में वन विभाग की भूमि का उपयोग करके किया गया था। यद्यपि विभाग से अपेक्षा थी कि वह परिशोधन कार्य करेगा, परंतु ऐसा नहीं किया गया। अब यदि कोई किसान अपने खेत में किसी पेड़ को छूता है तो उसकी निगरानी के लिए एक वन रक्षक को तैनात किया गया है। यहां राजस्व और वन विभाग को संयुक्त निर्णय लेने की आवश्यकता है ताकि वनों की कटाई न हो। इसके साथ ही जंगली जानवर किसानों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। पिछले दिनों वन विभाग ने सौरकुंपन जैसी बहुत अच्छी योजना शुरू की थी, जिसे फिर से शुरू किया जाना चाहिए ताकि किसानों और जानवरों के बीच टकराव से बचा जा सके। गोंदिया जिला दुग्ध संघ पिछले दो वर्षों से बंद है। 8 मिलियन संस्थानों को अभी तक यह सुविधा नहीं मिली है। इसलिए संस्थाओं को बकाया धनराशि का भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट में उच्च विशेषज्ञ वकील खड़ा करना चाहिए

सरकार ने हर विभाग में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ बनाया है। रोस्टर की जांच विभाग द्वारा की जाती है और स्थानीय सरकारी निकायों के कर्मचारियों की पदोन्नति/उन्नति इस पर निर्भर करती है। लेकिन यह सूची अनेकों में से अंतिम है। वर्षों से उनका उचित निरीक्षण नहीं किया गया है। इसलिए, कोई पदोन्नति और समयबद्ध पदोन्नति नहीं होती। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए. अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रोत्साहन अधिनियम 2004 में अधिनियमित किया गया। सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार को इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील खड़े करने चाहिए।

लाठी से मारकर किया घायल

गोंदिया-तिरोड़ा थाने के तहत घाटकुरोड़ा निवासी फिर्यादी राम राधेश्याम राऊत (27) के घर पर स्लैब डालने का काम जारी था. जगह नहीं होने के कारण वह सड़क पर आधे रास्ते पर मसाला बना रहा था. इसी दौरान तेढवा निवासी आरोपी मोहित रामप्रसाद चिरवदकर (10) अपना ट्रैक्टर निकाल कर कांक्रीट के मसाला के उपर से ट्रैक्टर लेकर गया. जिस पर फिर्यादी ने उसे तू एक मिनट रुक नहीं सकता क्या, ऐसा कहा. आरोपी ट्रैक्टर से नीचे उतरा व गालीगलौज करने लगा वहीं लाठी से फिर्यादी के सिर पर प्रहार कर उसे घायल कर दिया. फिर्यादी की शिकायत पर तिरोड़ा पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच हवलदार बांते कर रहे हैं.

ट्रैक्टर से बैटरी चोरी

गोंदिया- ग्रामीण थाने के तहत तुमखेड़ा वार्ड क्र. 3 निवासी फिर्यादी धनराज भुपतलाल बिसेन (48) ने अपना ट्रैक्टर घर के बाजू में रखा था. इसी बीच अज्ञात व्यक्ति ने ने ट्रैक्टर से बैटरी चुरा लिया. जिसकी कीमत 7 हजार रु. बताई गई है. फिर्यादी की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

राज्य में अधिकारियों, कर्मचारियों का सोशल मीडिया पर रिल्स व वीडियो अपलोड पर जल्द ही नयी नियमावली

» विधायक फुके के सवाल पर मुख्यमंत्री फड़नवीस का निर्णय

बुलंद गोंदिया (मुंबई)-विधानपरिषद में विधायक डॉ. परिणय फुके ने सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों की बढ़ती सक्रियता, सोशल मीडिया पर रिल्स अपलोड व अनियंत्रित व्यवहार को लेकर सरकार का ध्यानकेन्द्रित किया एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने व इसके लिए सख्त नियम और उनका क्रियान्वयन करने पर प्रश्न उठाया । फुके के इस प्रश्न को महत्वपूर्ण मानते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब देते हुए कहा। महाराष्ट्र में 1979 के सेवा शर्त नियमों में संशोधन करके अधिकारियों और कर्मचारियों के आचरण के संबंध में बहुत उपयुक्त नियम बनाए जाएंगे। इन नियमों को सेवा की शर्तों का हिस्सा बनाया जाएगा। इस संबंध में एक जीआर जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अनियंत्रित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विधायक डॉ. परिणय फुके ने विधान परिषद का ध्यान सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर बढ़ती सक्रियता की ओर आकर्षित किया। फुके ने कहा- आजकल ट्रेंड बन गया है कि अधिकारी, कर्मचारी जमकर रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे। सोशल मीडिया के माध्यम से यह छवि बनाई जा रही है कि जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक या प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस इंस्पेक्टर खुद ही पूरे क्षेत्र के सभी मामलों की देखरेख करते हैं। और वे ही राज्य के मामलों को संभाल रहे है, चला रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रिल्स अपलोड कर गली गली में सिंघम बन रहे है जिससे सरकारी यंत्रणाओं की बदनामी हो रही है।

विधायक डॉ. फुके ने सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। इसके लिए सख्त नियम और उनका क्रियान्वयन जरूरी है।

इससे पहले दिसंबर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा था। आज उन्होंने विधान परिषद सदन का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया।

फुके ने आगे कहा, महाराष्ट्र सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत पिछले तीन वर्षों में कितने कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? इसके अलावा, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बनाई गई रीलें अक्सर सरकार की बदनामी भी कराती हैं। इसलिए उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार इस पर नियंत्रण के लिए नया कानून बनाएगी या मौजूदा कानून में संशोधन करेगी ?

मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने विधायक डॉ. परिणय फुके द्वारा सदन में रखे इस महत्वपूर्ण सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि, वर्ष 1979 में वर्तमान सेवा नियम बनाये थे। उस समय सोशल मीडिया नहीं था। फुके ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है और कई जगह सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ पोस्ट करते हैं। वे अपने कर्तव्य का महिमामंडन करते प्रतीत होते हैं। इसलिए कुछ नियम आवश्यक हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार जनता से जुड़ने तथा नागरिक सहभागिता के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को बढ़ाने की आशा करती है। लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग का अध्ययन करने पर पता चला कि गुजरात और जम्मू-कश्मीर सरकारों ने इसके लिए अच्छे नियम बनाए हैं। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री अकादमी ने बहुत सख्त नियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में भी जल्द ही इसमें सुधार किया जाएगा।

गरिमा महिला संगठन ने मनाई छ. शिवाजी जयंती

गोंदिया-गरिमा महिला संगठन, परमात्मा एक नगर, सूर्याटोला ने तिथि अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आयोजित की. इस दिन संत श्री गाड़गेबाबा धर्मशाला सूर्याटोला के समीप स्थित श्री शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थल पर जाकर संगठन की पदाधिकारी व सदस्यों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिवादन किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता दीप्ति तावाड़े ने की. प्रमुख अतिथि के रूप में अरूण तुपकर थे. स्वागत गीत वर्षा मानकर ने प्रस्तुत किया. शिवरायांचा पालना, चारोली, शिवगर्जना आदि के साथ महिलाओं ने छत्रपति शिवाजी के शौर्य पर अपने सारगर्भित विचार रखे. संचालन धनंजयी काकड़े ने किया व आभार मंजू नखाते ने माना. सफलतार्थ संगठन अध्यक्ष मौसमी भालाधरे, उपाध्यक्ष मंजू नखाते, सचिव वर्षा मानकर, सह सचिव गीता मेश्राम, कोषाध्यक्ष धनंजयी काकड़े, संचालिका प्रीति केसलकर, सलाहकार प्रीति काले, सदस्य माधुरी कनोजे, अंजली पानतावने, पूनम रणदिवे, कुंदा खरकाटे, एकेश्वरी तावाड़े, वर्षा भोयर, कंचन सिरसे, स्मिता चौव्हान, सायली चौरे किरण उके, रेशमा रहमान, मनिषा पशीने, सपना हरिणखेड़े आदि ने प्रयास किया.

शासकीय तकनीकी महाविद्यालय में मनाया गया उमंग समारोह

बुलंद गोंदिया। शासकीय तकनीकी महाविद्यालय गोंदिया में वार्षिक पुनर्मिलन समारोह उमंग 2025-11 एवं 12 मार्च 2025 को मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में टियारा टेक्नोलॉजीज, गोंदिया के निदेशक आशीष गुप्ता, पूर्व छात्र बघेल उपस्थित थे। इस अवसर पर अतिथियों ने विद्यार्थियों का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया तथा उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। प्राचार्य डॉ. सी.डी गोलघाटे ने भी बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया। जिमखाना के उपाध्यक्ष डॉ. आर.एननिबुडे ने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। विद्यार्थियों ने सभी प्रतियोगिताओं में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इस समागम ने कलात्मक गुणों को अवसर प्रदान किया जो प्रत्येक विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी है। यह आयोजन गायन, नृत्य, नाटक, निबंध लेखन, खेल, रंगोली, मेहंदी और पोस्टर प्रतियोगिताओं के लिए बेहतरीन मंच साबित हुआ। उमंग 2025 ने सभी को एक ही लक्ष्य दिया- इसका लाभ उठाना और अपने स्वयं के छिपे हुए कलात्मक गुणों को प्राथमिकता देकर अपने जीवन में आगे बढ़ना। वार्षिक सम्मेलन के समन्वयक डॉ. सोनिया राउत ने कार्यक्रम का परिचय प्रस्तुत किया। जिमखाना सचिव, डॉ. जे.बी खुरपड़े, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्राध्यापक और सभी गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के सफल समापन के लिए सहयोग किया। इस सभा के समन्वयक डॉ. सोनिया राउत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।प्रो सह-समन्वयक वर्षा कापगते ने उपस्थित लोगों को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे।

पंचायती राज व्यवस्था से गांवों का विकास हुआ-लायकराम भेंडारकर

सरपंच सम्मेलन 15 ग्राम पंचायतों को किया सम्मानित

बुलंद गोंदिया। गोंदिया जिला परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडरकर ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि गांवों का विकास केवल इसलिए हुआ क्योंकि गांव, तालुका और जिले को पंचायत राज प्रणाली में शामिल किया गया था। वे नवेगांवबांध में आयोजित सरपंच सम्मेलन में अध्यक्ष पद से बोल रहे थे।

यह कार्यक्रम जिला परिषद के पंचायत विभाग द्वारा आयोजित किया गया था।इस अवसर पर मंच पर गोंदिया जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.,मुरुगनंथम उपाध्यक्ष सुरेश हर्षे, अध्यक्ष दीपाताई चंद्रिकापुरे, पूर्णिमाताई ढेंगे, रजनीताई कुंभारे, डॉ. लक्ष्मण भगत, अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. तानाजी लोखंडे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी फरेंद्र कुटीरकर, मधुकर वासनिक, पूर्व अध्यक्ष उषाताई मेंढे, पूर्व सभापति सविताई पुराम, सभी गट विकास अधिकारी तथा सभी पंचायत समितियों के सभापति जिला परिषद सदस्य, औरंगाबाद के भास्कर पेरे पाटिल, सांगली के श्रीधर कुलकर्णी तथा सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष बाहेकर उपस्थित थे।

भेंडारकर ने आगे कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी लगभग 82 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और हम इन सभी ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए उन्होंने आपसे पाटोदा ग्राम पंचायत की तरह सरकारी योजना अभियान में भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरुगनन्थम ने कहा कि अब ग्राम पंचायतें शासन की इकाई बन गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, सफाई, स्वच्छता, जल आपूर्ति और शिक्षा के संबंध में ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं और इसकी जिम्मेदारी सरपंच पर है। उन्होंने ग्राम पंचायतों से अपील की कि वे अपने गांवों को आत्मनिर्भर बनाएं क्योंकि उन्हें सरकार से पर्याप्त धनराशि मिल रही है। इस अवसर पर बोलते हुए उपाध्यक्ष हर्षे ने सरपंचों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियमों का अध्ययन करना आवश्यक है।

इस अवसर पर बोलते हुए सांगली के विस्तार अधिकारी ने पंचायत विकास सूचकांक के बारे में विस्तृत जानकारी दी और सतत विकास लक्ष्यों की 9 अवधारणाओं को समझाया। पाटोदा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच पेरे पाटिल ने कहा कि आज के समय में मानव जीवन छोटा होता जा रहा है और देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि राजनीति को एक तरफ रखकर जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी ग्राम पंचायत की आय 40 लाख रुपये है और इससे ग्राम पंचायत समृद्ध हुई है। पाटिल ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह देते हुए कहा कि उन्हें अपने गांवों को साफ रखना चाहिए, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए तथा बुजुर्गों से प्रेम करना चाहिए। पेरे पाटिल ने संत तुकाराम महाराज का अभंग सुनाकर सरपंचों को चुनौती दी और कहा कि अगर ऐसा करना है तो पहले ऐसा करना होगा। इस अवसर पर शासन से पुरस्कार प्राप्त करने वाली पंचायत समिति तिरोदा, ग्राम पंचायत भाजेपार, दाव्वा, दर्रेकसा, शिवनी, गंगाझरी, नाहरटोला, देवलगांव, भर्रेगांव, कमारगांव, कुंभीटोला, कातुरली, बोदरा, खोड़सिवनी, तिरखेड़ी, अंभोरा आदि ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मेरा पर्यावरण, जल गुणवत्ता आदि विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया गया।

इस अवसर पर ग्राम पंचायत विभाग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर वासनिक, अर्जुनी मोर की समूह विकास अधिकारी पल्लवी वाडेकर, सहायक समूह विकास अधिकारी ने मेहमानों का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत महापुरुषों की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग एवं स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम का संचालन विस्तार अधिकारी वैशाली खोबरागड़े एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार विशेषज्ञ अतुल गजभिये ने किया तथा उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिले के सरपंच, उपसरपंच और ग्राम पंचायत अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरुगनन्थम के मार्गदर्शन में उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासनिक, गुणवंत ठाकुर, पंकज पटेल, दिलीप चौधरी, सुनील चव्हाण, कविता राठौड़, ज्ञानेश्वर कनाडे, श्याम समरित, राजश्री गौतम, पृथ्वीराज कोल्हटकर, नरेश लांजेवार, प्रकाश तिरेले, रोहित बंसोड़, जगमोहन दास के साथ-साथ विस्तार अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया।

15 करोड़ की लागत का 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल का निर्माण होगा टीबी हॉस्पिटल की जमीन पर स्वास्थ्य सेवा के विकास दृष्टि से गोंदिया के लिए साबित होगा मिल का पत्थर -विधायक विनोद अग्रवाल

बुलंद गोंदिया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गोंदिया ने शहर एक और मुकाम हासिल करने जा रहा है। 15 करोड रुपए की लागत से 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल का निर्माण टीबी हॉस्पिटल की खाली जमीन पर होगा जिसके लिए विधायक विनोद अग्रवाल द्वारा निरंतर प्रयास किए गए थे। हॉस्पिटल मंजूर होने पर विनोद अग्रवाल ने कहा कि यह गोंदिया की स्वास्थ्य सेवा के लिए और एक मील का पत्थर साबित होगा। गौरतलब है की कोविड संकट के दौरान जब जिले में आधुनिक चिकित्सा के साथ-साथ योग, आयुष काढ़ा और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की जरूरत महसूस की गई, तब KTS और BGW अस्पतालों में इन सुविधाओं के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। इस चुनौती को देखते हुए विधायक विनोद अग्रवाल ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया और शासन से सतत संघर्ष करते हुए कई बैठकों के बाद टीबी टोली परिसर में टीबी हॉस्पिटल ग्राउंड की जमीन इस प्रकल्प के लिए आरक्षित करवाई।

15 करोड़ की मंजूरी, गोंदिया को मिलेगा 50 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल

जमीन की उपलब्धता के बाद विधायक विनोद अग्रवाल ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। उनके सतत प्रयासों से सरकार ने 15 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 50 बिस्तरों वाले आयुष अस्पताल को भी मंजूरी दे दी। इस अस्पताल के निर्माण से गोंदिया जिले को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी और जनता को आधुनिक चिकित्सा के साथ-साथ आयुष उपचार भी आसानी से उपलब्ध होंगे।

क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी इस नए आयुष अस्पताल में ?

आयुष अस्पताल में पारंपरिक और प्राकृतिक चिकित्सा की अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें शामिल हैं

आयुष उपचार पद्धति - आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और योग चिकित्सा,

होम्योपैथी- प्राकृतिक तरीके से रोगों का उपचार

पंचकर्म चिकित्सा -शरीर को रोगमुक्त करने की विशेष चिकित्सा

त्वचा विकार उपचार -चर्म रोगों के लिए आयुष पद्धति

कान, नाक और गला विकार उपचार

योग एवं ध्यान केंद्र -शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए

प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य विभाग -मातृ एवं शिशु देखभाल

बाह्य व आंतरिक रोगी विभाग -समग्र आयुष चिकित्सा के लिए

गोंदिया के स्वास्थ्य विकास में मील का पत्थर

विधायक विनोद अग्रवाल ने इस अस्पताल की स्वीकृति दिलाकर जिले की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। यह अस्पताल न केवल जिले के नागरिकों के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए भी लाभदायक साबित होगा।

श्रीराम जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष पद पर हेमेंद्र पोद्दार की नियुक्ति

बुलंद गोंदिया। गोंदिया शहर के श्री राम जन्मोत्सव समिति के नए अध्यक्ष पद व आगामी जन्मोत्सव पर्व को लेकर श्री कृष्णा गोरक्षण गौशाला (पंजारा पोल) में सकल समाज की सभा आयोजित की गई थी जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर हेमेंद्र पोद्दार की नियुक्ति की गई।

गौरतलब हैं की 550 वर्षों के संघर्ष के पश्चात अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण होने तथा रामलला की स्थापना के पश्चात राम जन्मोत्सव का पर्व बड़े धूमधाम से संपूर्ण देश में आयोजित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि गोंदिया शहर में 50 वर्षों से अधिक समय से राम जन्मोत्सव पर्व व शोभायात्रा श्री राम जन्मोत्सव समिति के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है।

आगामी रामनवमी का पर्व जोर-जोर से मनाने के लिए रविवार 16 मार्च को पिंडकेपार रोड स्थित श्री कृष्ण गौशाला पाजरापोल में सकल हिंदू समाज की सभा श्री राम जन्मोत्सव समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी गणेश अग्रवाल की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित की गई थी जिसमें बड़ी संख्या में सभी समाज के प्रतिनिधि वह कार्यकर्ता उपस्थित थे।

आयोजित सभा में सर्वप्रथम नए अध्यक्ष के निर्वाचन का प्रस्ताव रखा गया जिसमें हेमेंद्र सूरजमल पोद्दार के नाम का प्रस्ताव आने पर उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा इसका अनुमोदन कर सर्वसम्मति से हेमेंद्र पोद्दार को आगामी 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर नई कार्यकारिणी गठित करने का सर्वसम्मति से अधिकार दिया। तथा जल्द ही नई कार्यकारिणी का गठन कर आगामी राम जन्मोत्सव के कार्यक्रमो की रूपरेखा की जानकारी दी जाएगी। आयोजित सभा में प्रमुख रूप से गणेश अग्रवाल ,हेमेंद्र पोद्दार ,आसित अग्रवाल, पंकज यादव, राजू नोतानी, नवीन अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, जयंत अग्रवाल, देवेश मिश्रा, नितिन जिंदल, महेश आहूजा, जय चौरसिया, वीरेंद्र जैसवाल, संदीप श्रीवास, राजेश कनोजिया, सचिन चौरसिया, अमित झा, अंकित कुलकर्णी, भूपेंद्र श्रीवास, अजय यादव, स्नेहल पटेल, शरद काथरानी, हर्षल पवार, नागेश दुबे, रोहित श्रीपात्रे, मनोज श्रीवास, राहुल, स्वामी, अशोक अरखेल, बबलू गभने, संस्कार इंदनी, दिनेश द्विवेदी, बंटी मिश्रा, संजय पटेल, प्रीतम लिल्हारे, दिनेश इंदनी, अपूर्व अग्रवाल, आनंद जैन, हरीश तीर्थनी, चुन्नी चौरावर, योगेश पसीने, विनीत मोहिते, बबलू वासनिक, महेश कोठारी , बिपिन बावीशी , उपेंद्र लंजेवार, जीतेन्द्र अग्रवाल, अपूर्व मेठी, नरेंद्र अग्रवाल, विनोद चांदवाणी, नविन टांक, राजेश परमार, चन्दन पंचारिया, जलाराम गंभीर, सुरेश जी राठौड़, तुषार घडोले, काव्य श्रीवास, वैभव बेलगे, हितेश कोड़वानी, किशोर देशकर, श्याम खंडेलवाल, आयुष तुम्बी, मोनू गेड़ाम, प्रितेश रामत्तेकर, संदीप आसत्कर, वीरेंद्र बिसेन, सौरभ बजाज, रवि रामत्तेकर, धर्मेन्द्र अग्रवाल, अंकेश तिवारी, हरीश अग्रवाल, नितेश गुरदे, राम नोटानी, विजय आहूजा, बिशनलाल अग्रवाल, मुन्नू तिवारी, राकेश आहूजा, कमलेश भागदेव, राजेश चौहान, ऋषिकांत साहू, पंकज पंडित, राजकुमार भवानी, रूक्र मोटवानी, कैलाश अग्रवाल, पुष्कर बरापात्रे, अंकित कुलकरणी, राजा मिश्रा, संजय श्रीवास्तव, सोनू चंद्रवंशी, दरयानी असवाणी,दिनेश जी लिल्हारे, अनूप मानिकपुरी, मुकेश दाहिकार, ओमप्रकाश भण्डारकार, रोहित भण्डारकार, सौम्य कवल, मितेश परमार, मनोज हरदे, अजय शर्मा, लोकेश यादव आदि उपस्थित थे। आये हुए सभी सदस्यों का नितिन जिंदल ने आभार प्रकट किया ।

मनोहरभाई पटेल अकॅडमी व दिशा संस्था के संयुक्त तत्वाधान मे मधुमेह जागृती मेले की 25 वी वर्षगाठ

बुलंद गोंदिया। मनोहरभाई पटेल अकॅडमी व दिशा संस्था के संयुक्त तत्वाधान मे गोंदिया जिले के मधुमेहीओं के लिए मधुमेह जागृती मेले के पच्चीस वर्ष पुरे होने पर आयोजित उद्घाटन समारोह एन.एम.डी. महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत डॉक्टर सुनील गुप्ता के हस्ते पूर्व विधायक राजेंद्र जैन की अध्यक्षता मे संपन्न हुआ ।डॉक्टर देवाशीष चटर्जी के मार्गदर्शन मे सतत पच्चीस वर्षे से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आहार विशेषण डॉक्टर कविता गुप्ता नागपूर व उनकी पूरी टीम द्वारा डायबिटीस के विषय मे जानकारी देकर उस पर उपयुक्त तरीके से मार्गदर्शन किया जाता हैद्य अनुठे तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन होता है तथा मधुमेहिओं को जागृत कर जीवन आसानी से जीने के तरीके बतायें जाते है, डॉक्टर यादव कुदळे, विनोद अग्रवाल व दिशा संस्था के सभी लोग जागृती के कार्य करते है। हॅलो डायबिटीज इस कार्यक्रम को नागपूर से देश की अलग अलग हिस्सों मे जागृती करणे का कार्य डॉक्टर सुनील गुप्ता करते है। इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक डॉक्टर देवाशीष चटर्जी ने व अध्यक्षता पूर्व

विधायक राजेंद्र जैन ने किया।

जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण 25 मार्च तक जमा करे आवेदन

बुलंद गोंदिया। आदिवासी समुदायों के उम्मीदवारों को पूर्व-प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने मुख्य रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में यह योजना शुरू की है। प्रतियोगी परीक्षा पूर्व उत्तीर्ण करने के उद्देश्य से आदिवासी अभ्यर्थियों को कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, देवरी कार्यालय के माध्यम से जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। देवरी में प्रशिक्षण केंद्र जनवरी 1986 से कार्यरत है। उक्त कार्यालय की वर्ष 2025-26 हेतु प्रतियोगी परीक्षा सूचना एवं मार्गदर्शन का प्रथम सत्र 1 अप्रैल से 15 जुलाई 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आदिवासी समुदाय के अभ्यर्थी अपना आवेदन शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी के साथ 25 मार्च 2025 तक देवरी कार्यालय में जमा कराएं।

प्रशिक्षुओं की शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं इस प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के पास कम से कम एस.एस.सी. डिग्री होनी चाहिए। अवश्य ही उत्तीर्ण हुआ होगा। उच्च शैक्षिक योग्यता वाले तथा टाइपिस्ट/कम्प्यूटर/स्टाफ परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी जनजातीय वर्ग से होना चाहिए, इसके लिए पुरुष एवं महिला दोनों पात्र हैं। अभ्यर्थियों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी गोंदिया और भंडारा, दोनों जिलों में से किसी एक का निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी को पहले कभी इस प्रशिक्षण का लाभ नहीं मिला होगा। अभ्यर्थी के पास रोजगार एवं स्वरोजगार कार्यालय से प्राप्त ऑनलाइन पंजीकरण कार्ड होना चाहिए। बैंक खाते और आधार कार्ड के साथ पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी।

प्रशिक्षण अवधि

इस योजना के तहत प्रशिक्षण अवधि तीन महीने और पंद्रह दिन यानी 1 अप्रैल से 15 जुलाई, 2025 तक होगी। चयनित अभ्यर्थियों को देवरी में अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

वजीफा

प्रशिक्षण के लिए चयनित प्रशिक्षुओं को 1,000 रुपये प्रति माह का वजीफा दिया जाएगा। यह जानकारी कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता मार्गदर्शन अधिकारी देवरी ने दी है।

रेत तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक नयी रेत नीति- राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले

बुलंद गोंदिया (मुंबई)- रेत तस्करी पर नियंत्रण के लिए वर्तमान में राज्य में राजस्व एवं पुलिस बल द्वारा संयुक्त कार्यवाही की जा रही है। लेकिन राज्य में रेत माफिया और रेत तस्करी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस कारण से, राज्य सरकार एक व्यापक रेत नीति तैयार करने जा रही है, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधान परिषद मे इसकी जानकारी दी । मंत्री बावनकुले विपक्ष के नेता अंबादास दानवे द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए बोल रहे थे। इस अवसर पर सदस्य प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे और एकनाथ खडसे ने चर्चा में भाग लिया। मंत्री बावनकुले ने आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य में रेत माफियाओं और रेत तस्करों को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोदावरी घाटी में रेत खनन के संबंध में 7 दिनों के भीतर जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार नई रेत नीति पर काम कर रही है और इसके अनुसार अब एम सैंड यानी पत्थर से बनी रेत के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए राज्य के हर जिले में रेत क्रशर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक जिले में कम से कम 50 से 100 ऐसे क्रशर स्थापित करने की योजना है। इससे रेत की उपलब्धता बढ़ेगी और रेत की आपूर्ति और मांग के बीच मौजूदा अंतर कम होगा। इससे रेत माफिया पर स्वत: नियंत्रण हो जाएगा। रेत नीति में रेत तस्करी के संबंध में राजस्व और पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई के समान अधिकार देने का भी प्रावधान किया जाएगा।

रेत नीति निर्माण में जनता के सुझावों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, मंत्री बावनकुले ने सदन को यह भी बताया कि रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में सक्शन पंपों का उपयोग करके रेत निकालने की जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सदस्य शशिकांत शिंदे द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, मंत्री बावनकुले ने कहा कि सातारा जिले के खटाव के मामले में 7 दिनों के भीतर विभागीय आयुक्त द्वारा जांच की जाएगी और जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कृषि उत्पन्न बाजार समिति संचालक धनलाल ठाकरे की भ्रष्टाचार के आरोप में सदस्यता रद्द 34 फर्जी नियुक्तिया वेतन के 3 करोड़ 82 लाख रुपए की वसूली का आदेश

बुलंद गोंदिया।

गोंदिया कृषि उत्पन्न बाजार समिति में 34 अस्थाई कर्मचारियों की नियमबाहय नियुक्ति के आदेश के मामले में जिला उप निबंधक सहकारी प्रशांत सोनारकर द्वारा मामले की जांच कार्यवाही करते हुए संचालक धनलाल ठाकरे की संचालक पद से सदस्यता रद्द कर कर्मचारियों को दिए गए वेतन की राशि के तीन करोड़ 82 लाख 64135 रुपए की वसूली का आदेश का दिया है। गौरतलब है की कृषि उत्पन्न बाजार समिति तत्कालीन संचालक मंडल के उपसभापति धनलाल ठाकरे द्वारा अपने हस्ताक्षर से 34 अस्थाई कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश व पांचवें व छठवें वेतन आयोग की वेतन श्रेणी लागू करने का आदेश जारी किया गया था । इसके लिए जिलाउप निबंधन विभाग सहकारी संस्था गोंदिया के कार्यालय से किसी भी प्रकार की निम्य नुसार लिखित में मंजूरी प्राप्त नहीं की थी जो की नियम के बाहर है। शिकायत के पश्चात जिला उपनिवंधक प्रशांत सोनारकर द्वारा मामले की जांच कर वर्तमान संचालक व तत्कालीन उपसभापति धनलाल ठाकरे को दोषी करार दिया तथा दोषी करार देने के पश्चात धनलाल ठाकरे की सदस्यता रद्द करने के साथ ही तत्कालीन संचालक मंडल व धनलाल ठाकरे से कर्मचारियों को दिए गए वेतन के तीन करोड़ 82 लाख 64135 की वसूली का भी आदेश दिया है

34 फर्जी नियुक्तियाँ, करोड़ों का नुकसान

जांच में पाया गया कि श्री ठाकरे ने अपने कार्यकाल में नियमों को ताक पर रखकर 34 अस्थायी कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति की। यही नहीं, पहले उन्हें पाँचवीं और फिर छठी वेतनश्रेणी लागू कर दी, जिससे समिति को कुल 3 करोड़ 82 लाख 64 हजार 135 रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ।

पद का दुरुपयोग और शासन को गुमराह करने का आरोप

जिला उपनिबंधक द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि ठाकरे ने अपने पद का गंभीर दुरुपयोग किया और शासन को गुमराह करते हुए अनियमित नियुक्तियाँ की। यह पूरी प्रक्रिया न केवल नियमों के खिलाफ थी, बल्कि समिति के वित्तीय संतुलन को भी बुरी तरह प्रभावित किया।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, जब्ती और वसूली की तैयारी

प्रशासन अब इस घोटाले में जब्ती और वसूली की कार्रवाई की भी तैयारी कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति पर उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में इस तरह की धांधली न दोहराई जा सके।

जनता ने बदलाव किया, घोटाले उजागर हुए

गौरतलब है कि दो वर्ष पूर्व हुए कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव में जनता ने पूर्व संचालक मंडल की भ्रष्ट गतिविधियों से त्रस्त होकर तख्तापलट किया था। नए संचालक मंडल के कार्यकाल में लगातार पुराने घोटालों की जांच करवाई जा रही है और इसी क्रम में यह बड़ा खुलासा हुआ।

आगे क्या ?

प्रशासन का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और भविष्य में और भी घोटाले उजागर हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि अधिकारियों द्वारा दोषियों पर किस तरह की सख्त कार्रवाई की जाती है और कितनी जल्दी जनता को न्याय मिलता है।

चेक बाउंस मामले में 6 महीने की सजा,1.80 लाख का जुर्माना ठोका

गोंदिया-देवरी के सिविल न्यायाधीश व प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को छह माह के कारावास व 1 लाख 80 हजार रु. के जुर्माने की सजा सुनाई है. न्यायालय द्वारा सजा और जुर्माना लगाए गए आरोपी का नाम राजकुमार मेश्राम बताया गया है. देवरी के व्यवसायी विनोद कुमार अग्रवाल के मकान बनाने का समझौता ठेकेदार राजकुमार मेश्राम ने किया था. लेकिन मेश्राम ने समझौते के अनुसार काम नहीं किया. इसके अलावा, उसने अग्रवाल से और पैसे ले लिए और बीच में ही काम छोड़ दिया. जब अग्रवाल ने राजकुमार मेश्राम से अपने पैसे वापस मांगे, तो मेश्राम ने अग्रवाल को एक चेक दिया. क्योंकि मेश्राम ने समझौते के अनुसार काम नहीं किया था. लेकिन जब उसने चेक बैंक में जमा किया तो वह बाउंस हो गया. इस मामले में विनोद कुमार अग्रवाल ने देवरी दिवानी न्यायालय में याचिका दायर की थी.

मामले की सुनवाई करते हुए सभी साक्ष्यों का सत्यापन करने के बाद देवरी के दिवाणी न्यायाधीश व प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी ने आरोपी राजकुमार मेश्राम को छह माह के कारावास और 1 लाख 80 हजार रु. के जुर्माने की सजा सुनाई. इस मामले में फिर्यादी विनोदकुमार अग्रवाल की ओर से एड. भुषणकुमार मस्करे, एड. प्रीति मस्करे, एड. संयोग बंसोड, एड. रेश्मा माहुलकर ने पैरवी की

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल द्वारा बुलंद गोंदिया साप्ताहिक समाचार पत्र भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरुनानक वार्ड, गोंदिया ता.जि.गोंदिया से मुद्रित व बुलंद गोंदिया भवन, जगन्नाथ मंदिर के पास गौशाला वार्ड, गोंदिया-४४१६०१, ता.जि.गोंदिया से प्रकाशित । संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल, मो.क्र.९४०५२४४६६८। (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) प्रकाशित किये गये समाचार व लेख से संपादक सहमत है। न्यायालय क्षेत्र गोंदिया ।